(b) Land surplus to the requirements of Railways is made available to the Collectors by the Railway Ministry for letting it out for cultivation. While allotting such lands preference is given to the landless agricultural labourers and then to dependants of soldiers killed in action.

According to the recommendation of the Working Group on Land Utilisation, all the vacant forest lands suitable for plantation, are being afforested in a planned manner by maximising the use of "Taungya" method. Under this system, selected areas are leased out by auction for sowing crops along with forest plantation for 3-4 years and smaller areas are given preferentially to local landless inhabitants including the Harijans. Water-lobbed areas are, however leased out on short term year to year basis for Boro and Melon cultivation.

उत्तर प्रदेश में तारघर

958. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में तारघरों की जिलावार संख्या कितनी है ;

(ख) कितने तारघरों में सरकार द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में तारें भेजने की सुविधायें प्रदान की गई हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने तारघरों में केवल अंग्रेजी में ही तार भेजने की सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये** संख्या L T-1450/68]

(ख) उत्तर प्रदेश में सभी 1055 तारघरों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तार भेजने के लिए सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) सभी तारघर अंग्रेजी और देवनागरी में तार स्वीकार करते हैं।

अफसरों के निवास स्थानों पर लगाये गये टेलीफोनों का हटाया जाना

959. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में कुछ श्रेणियों के अधिकारियों के निवास स्थानों पर लगाये गये सरकारी टेलीफोनों को हटाया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त सुझाव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कोटा के तारघरों के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

960. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को कोटा तारघर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों में से तारों के वितरण पर लगे हुए कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक उन कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कितने रुपये दिये गये ; और

(घ) उक्त अवधि में प्रत्येक कर्मचारी को पृथक-पृथक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कितने-कितने रुपये दिये गये ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 60

(ख) 13

(ग) 71,044 रुपये।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-1451/68]**

मध्य प्रदेश सरकार को चीनी की सप्लाई

961. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि उस राज्य को दिये जाने वाले चीनी के कोटे में वहां की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य के चीनी कोटे में वृद्धि कर दी है ; और

(ग) उस राज्य के नियत कोटे से अधिक चीनी की सप्लाई की उनकी मांग में से कितने टन चीनी केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथापि राज्य सरकार को 741 मीटरी टन का एक तदर्थ अतिरिक्त कोटा उत्सवों, शादियों, धार्मिक समारोहों आदि हेतु मार्च-अप्रैल, अप्रैल-मई, और मई जून 1968 की प्रत्येक मासिक अवधि के लिये आवंटित किया गया था, जब कि ऐसे ही तदर्थ कोटे अन्य राज्यों को भी आवंटित किये गये थे ।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान दूर-संचार का विशेष प्रबन्ध

962. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 मई से 31 मई, 1968 तक प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच दूर-संचार के विशेष प्रबंध किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ दूर-संचार के विशेष प्रबन्ध किये गये थे; और

(ग) दूर-संचार के विशेष प्रबंध के अन्तर्गत किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई थीं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा मलयेशिया ।

(ग) (i) पत्रकारों तथा प्रधान मंत्री के दल द्वारा भेजे गये परिधान की बढ़ी हुई मात्रा को संभालने